

## दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 03-11-2024

### विषय सूची

पारस्परिकता (mutualism) का सिद्धांत  
मुद्रा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स को चेतावनी  
तटीय संकट: भारत की 33.6% तटरेखा कटाव से खतरे में है  
राष्ट्रीय बीज कांग्रेस (NSC) का 13वां संस्करण  
बागवानी उत्पादकता के लिए ADB के साथ भारत का समझौता

### संक्षिप्त समाचार

साँची का महान स्तूप  
पेरू में नाजूका जियोग्लिफ्स (Nazca Geoglyphs)  
ऑक्सफोर्ड ने प्रगति (PRAGATI) प्लेटफॉर्म की सराहना की  
रबी फसल के लिए संभावनाएँ और चिंताएँ  
विंडफॉल टैक्स/अप्रत्याशित कर (Windfall Tax)  
वधावन बंदरगाह  
अभ्यास सिनबैक्स (Exercise CINBAX)  
अग्नि योद्धा अभ्यास (XAW-2024) [Exercise AGNI WARRIOR (XAW-2024)]  
अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट (AGWP)  
नागालैंड राज्य दिवस

## पारस्परिकता(mutualism) का सिद्धांत

### सन्दर्भ

- शब्द "पारस्परिकता(mutualism)" फ्रांसीसी दार्शनिक पियरे-जोसेफ प्राउडॉन द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में पूंजीवाद और अधिनायकवाद की उनकी व्यापक आलोचना के हिस्से के रूप में दिया गया था।

### पारस्परिकता(mutualism)

- **सहकारी स्वामित्व:** यह एक आर्थिक तथा सामाजिक सिद्धांत है जो स्वैच्छिक सहयोग, पारस्परिकता और वस्तुओं एवं सेवाओं के उचित आदान-प्रदान पर बल देता है।
  - यह एक ऐसे समाज का समर्थन करता है जहां व्यक्ति और समुदाय सभी के लाभ के लिए सहकारी स्वामित्व, विकेंद्रीकरण और सामूहिक रूप से भूमि या उपकरण जैसे उत्पादक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं।
- **प्राधिकार से मुक्त:** ऐसी प्रणालियाँ केंद्रीय प्राधिकार और पूंजीवादी शोषण से मुक्त होंगी।
- **पारस्परिकता और संपत्ति:** इसमें स्वामित्व के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान नहीं किया गया।
  - यह संचय और लाभ के बजाय उपयोग के आधार पर स्वामित्व के एक रूप पर बल देता है।
  - औजारों या भूमि का स्वामित्व स्वीकार्य है, बशर्ते इससे दूसरों का शोषण न हो।

### पारस्परिकता और अराजकतावाद

- **अराजकतावाद(Anarchism):**
  - व्यक्तिगत अराजकतावादी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर बल देते हैं, राज्य नियंत्रण से व्यक्ति की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - सामाजिक अराजकतावादी समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन एवं समाज के संगठन का समर्थन करते हैं।
- सहकारी सिद्धांतों के आधार पर एक पारस्परिक समाज को राज्य के बिना संगठित किया जा सकता है, जहां लोग स्वतंत्र रूप से अनुबंध और पारस्परिक आदान-प्रदान में प्रवेश करते हैं, इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक जिम्मेदारी दोनों का मिश्रण होता है।

### पारस्परिकता की आलोचना

- **पूंजीवाद को चुनौती देने के लिए कमजोर सिद्धांत:** छोटे पैमाने पर संपत्ति के स्वामित्व पर इसकी निर्भरता पूंजीवादी व्यवस्था की व्यापक संरचनात्मक असमानताओं को पर्याप्त रूप से चुनौती नहीं दे सकती है।
  - यह धन और शक्ति की एकाग्रता को संबोधित करने में विफल रहता है जो आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्निहित है।
- **अत्यधिक आदर्शवादी:** आलोचक स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर एक समतावादी समाज बनाने की व्यवहार्यता पर प्रश्न उठाते हैं, यह सुझाव देते हुए कि इसे बड़े पैमाने पर लागू करना बहुत आदर्शवादी या कठिन हो सकता है।
- **वर्ग संघर्ष की अनदेखी:** इस सिद्धांत ने वर्ग संघर्ष की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज़ कर दिया है, जहां छोटे उत्पादकों को बड़ी कंपनियों द्वारा बाहर कर दिया जाता है।

### निष्कर्ष

- इन आलोचनाओं के बावजूद, पारस्परिकता एक कट्टरपंथी सिद्धांत बना हुआ है जो पूंजीवादी शोषण और अधिनायकवाद दोनों का विकल्प प्रदान करता है।
- इन विचारों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा और शोषण के बजाय आपसी सहायता एवं सहयोग पर आधारित आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण को बढ़ावा देना है।

- पारस्परिकता एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती है जहां व्यक्ति समुदाय और पारस्परिक सम्मान की भावना बनाए रखते हुए अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हों।

Source: TH

## मुद्रा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स को चेतावनी

### समाचार में

- अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) को चेतावनी दी कि यदि वे नई ब्रिक्स मुद्रा बनाते हैं या अमेरिकी डॉलर को वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा।

### ब्रिक्स मुद्रा और अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व:

- बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर की कमी के मद्देनजर ब्रिक्स देश वैश्विक व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर के विकल्प खोज रहे हैं।
  - अलग-अलग आर्थिक संरचनाएं, विभिन्न मौद्रिक एवं व्यापार नीतियां, और अन्य जटिलताएं एक सामान्य ब्रिक्स मुद्रा के निर्माण को दीर्घकालिक लक्ष्य बनाती हैं।

#### वैश्विक मुद्रा रुझान:

- IMF की COFER रिपोर्ट वैश्विक भंडार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी में गिरावट दर्शाती है, जबकि गैर-पारंपरिक मुद्राएं (जैसे, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, चीनी रेंमिन्बी) बाजार हिस्सेदारी प्राप्त कर रही हैं।
- चीन द्वारा रेनमिनबी अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रयास भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भंडार का उसका हिस्सा रुका हुआ है।

### भारत का दृष्टिकोण:

- भारत हाल ही में लॉन्च किए गए ब्रिक्स पे कार्ड में एकीकरण की खोज कर रहा है, जिसे टोकन खुदरा भुगतान की सुविधा, पर्यटन को बढ़ाने और वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- भारत का लक्ष्य अमेरिकी डॉलर को विस्थापित करना नहीं है, बल्कि व्यापार भागीदारों की मुद्रा की कमी, अवरुद्ध वित्तीय चैनल और "हथियारबंद" मुद्राओं से संबंधित मुद्दों जैसी व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करना है।
- **आर्थिक कूटनीति पर ध्यान:** भारत व्यापार भुगतान को रुपये में निपटाने जैसे व्यावहारिक समाधानों का समर्थन करता है, विशेषकर उन देशों के मामले में जो डॉलर में तरलता के मुद्दों या प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं।
- भारत अमेरिकी डॉलर द्वारा प्रदान की गई स्थिरता को स्वीकार करता है और तत्काल डी-डॉलरीकरण(de-dollarization) की मांग नहीं करता है।
  - भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स का लक्ष्य वैश्विक संस्थानों को प्रतिस्थापित करना नहीं होना चाहिए।

### रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए पहल

- **विशेष वोस्ट्रो खाते:** रुपये-आधारित व्यापार निपटान की सुविधा के लिए, भारत ने विनिमय दर जोखिम को कम करने, लेनदेन लागत को कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए विशेष वोस्ट्रो खाते प्रस्तुत किए हैं।

- **ग्लोबल साउथ को लक्षित करना:** भारत का लक्ष्य डॉलर की कमी वाले देशों (जैसे, श्रीलंका, मालदीव) और पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना करने वाले देशों (जैसे, रूस, वेनेजुएला) का समर्थन करना है।
- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):** भारत सीमा पार से भुगतान को सुव्यवस्थित करने, सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने, मध्यस्थ बैंकों पर निर्भरता कम करने और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपनी CBDC पहल को आगे बढ़ा रहा है।

### अमेरिकी डॉलर पर दृष्टिकोण

- भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी डॉलर से बचना भारत की नीति का भाग नहीं है, लेकिन कुछ देशों के साथ व्यापार को जटिल बनाने वाली अमेरिकी नीतियों के कारण विशिष्ट मामलों में विकल्प खोजने का प्रयास किया जाता है।
  - भारत का डॉलर के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य नहीं है, लेकिन वह बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करता है जो मुद्राओं और आर्थिक लेनदेन में परिलक्षित होता है।

### रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार में चुनौतियाँ

- प्रयासों के बावजूद, भारतीय बैंकों के अमेरिकी प्रतिबंधों के भय और रूस के साथ असंतुलित व्यापार संबंधों के कारण रूस के साथ भारत का रुपये में व्यापार कम बना हुआ है।
- रूस के पास रुपयों का बड़ा भंडार है लेकिन वह इसका प्रयोग व्यापार निपटाने के बजाय भारतीय शेयरों और बांडों में निवेश के लिए करता है।
- **चीन का दृष्टिकोण:** रूस और चीन के बीच घरेलू मुद्राओं (रूबल और युआन) में व्यापार उभरा है, 90% से अधिक व्यापार अब इन मुद्राओं में तय होता है।

### ब्रिक्स मुद्रा का भविष्य और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य:

- चीन ब्रिक्स मुद्रा पहल पर प्रभुत्वशाली हो सकता है, जो ब्लॉक के अंदर शक्ति संतुलन को परिवर्तित कर सकता है।
- भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ना चाहिए।
- भारत को ब्रिक्स के अंदर वित्तीय सुधारों का समर्थन करना चाहिए लेकिन अपनी रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहिए।
  - डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) और UPI जैसे प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के प्रयास भारत को ब्रिक्स मुद्रा पहल में अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकते हैं।

Source: IE

### तटीय संकट: भारत की 33.6% तटरेखा कटाव से खतरे में है

#### सन्दर्भ

- हाल के लोकसभा सत्र में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रकटीकरण किया कि भारत की लगभग एक तिहाई तटरेखा को कटाव का खतरा है, जो व्यापक तटीय प्रबंधन रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

#### तटीय कटाव के बारे में

- यह भारत की व्यापक तटरेखा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जो 7,500 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है।

- भारतीय मुख्य भूमि तट में 9 तटीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश (UTs) शामिल हैं जिनमें 66 तटीय जिले हैं।
- तट की आकृति विज्ञान में 43% रेतीला समुद्र तट, 11% चट्टानी तट, 36% कीचड़युक्त समतल भाग, 10% दलदली तट, 97 प्रमुख मुहाना और 34 लैगून शामिल हैं।

Sl. No	State	Landforms and features
<b>East coast of India</b>		
1	Tamil Nadu	Deltas, long narrow beaches, spits, tidal flats, mangroves, coral reefs, sand dunes, Ridge swale complex etc.
2	Andhra Pradesh	Deltas, long narrow beaches, spits, mangroves, cliffs, long sand dunes, Ridge swale complex etc.
3	Odisha	Deltas, long beaches, spits, tidal flats, long sand dunes, ridges etc.
4	West Bengal	Large delta, very thick mangroves, tidal channels, islands, dunes, tidal flat, beaches etc
<b>West Coast of India</b>		
5	Kerala	Estuaries, lagoons, barriers, spits, dunes, tombolo, cliff, beaches etc
6	Karnataka & Goa	Estuaries, spits, sand dunes, tombolo, cliff, wave cut platforms, beaches etc
7	Maharashtra	Estuaries, cliffs, small sand dunes, tombolo, cliff, wave cut platforms, pocket beaches etc
8	Gujarat	Marshy land, tidal flats, estuaries, cliffs, mud flats, mangroves wave cut platforms, beaches etc.

- नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (NCCR) (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय) के अनुसार, भारत की लगभग 33.6% तटरेखा कटाव की चपेट में है, 26.9% अभिवृद्धि (वृद्धि) का अनुभव कर रहा है, और 39.6% स्थिर बनी हुई है।

### तटीय कटाव की आशंका वाले राज्य

- **कर्नाटक:** लोकसभा में प्रस्तुत डेटा विशेष रूप से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले पर केंद्रित था, जहां पिछले तीन दशकों में 36.66 किमी समुद्र तट का लगभग 48.4% नष्ट हो गया है।
  - इस क्षेत्र की दुर्दशा व्यापक राष्ट्रीय मुद्दे का एक सूक्ष्म रूप है, जिसमें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग डिग्री के क्षरण देखे गए हैं।

### अन्य राज्य

- **पश्चिम बंगाल:** राज्य की लगभग 60.5% तटरेखा कटाव से प्रभावित है, जिसका सुंदरबन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
- **केरल:** केरल की लगभग 46.4% तटरेखा कटाव का सामना कर रही है, जिसके स्थानीय समुदायों और पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर परिणाम हो रहे हैं।
- **तमिलनाडु:** कटाव से समुद्र तट का 42.7% हिस्सा प्रभावित हुआ है, जिससे तटीय बुनियादी ढांचे और आजीविका के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।

### तटीय कटाव के कारण

- **प्राकृतिक कारक:**

- **तरंग क्रिया:** निरंतर तरंग क्रिया तटरेखा को नष्ट कर देती है, विशेषकर उच्च ज्वार और तूफान के दौरान।
- **समुद्र-स्तर में वृद्धि:** जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र-स्तर में वृद्धि से तटीय बाढ़ और कटाव की आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ जाती है।
- **तूफानी लहरें:** चक्रवात और तूफानी लहरें विशेष रूप से निचले तटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कटाव का कारण बनती हैं।
- **मानवजनित कारक:**
  - **तटीय विकास:** बंदरगाह, हार्बर और समुद्री दीवारें जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्राकृतिक तलछट प्रवाह को बाधित करती हैं और कटाव को बढ़ा देती हैं।
  - **रेत खनन:** समुद्र तटों और नदी तलों से अवैध रेत खनन से तट पर रेत की प्राकृतिक पुनःपूर्ति कम हो जाती है।
  - **वनों की कटाई:** मैंग्रोव और तटीय वनस्पति को हटाने से कटाव के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर हो जाती है।

### तटीय कटाव के प्रभाव

- **भूमि की हानि:** तटीय कटाव से मूल्यवान भूमि की हानि होती है, जिससे कृषि और बस्तियाँ प्रभावित होती हैं।
- **समुदायों का विस्थापन:** कटाव तटीय समुदायों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जिससे सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **बुनियादी ढांचे को हानि:** तट के पास की सड़कों, पुलों और इमारतों को हानि या विनाश का जोखिम है।
- **जैव विविधता की हानि:** मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों और आर्द्रभूमि सहित तटीय आवासों का क्षरण हो रहा है, जिससे समुद्री जैव विविधता प्रभावित हो रही है।

### संबंधित पहल और शमन उपाय

- **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP):** गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित, इस विश्व बैंक-सहायता प्राप्त परियोजना का उद्देश्य सतत प्रथाओं के माध्यम से तटीय एवं समुद्री पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना है।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना (2019):** इसका उद्देश्य कटाव नियंत्रण उपायों की अनुमति देते हुए मछुआरों और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना, तटीय हिस्सों का संरक्षण एवं सुरक्षा करना है।
  - यह भारत की तटरेखा को अतिक्रमण और कटाव से बचाने के लिए तटीय क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के साथ नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) प्रदान करता है।
- **तटीय भेद्यता सूचकांक (CVI):** भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने विभिन्न मापदंडों के आधार पर विभिन्न तटीय क्षेत्रों की भेद्यता का आकलन और मानचित्रण करने के लिए CVI विकसित किया है।
- **बहु-खतरा भेद्यता मानचित्र:** INCOIS ने तटीय खतरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विस्तृत मानचित्र विकसित किए हैं।

### नवोन्वेषी इंजीनियरिंग समाधान

- **कृत्रिम चट्टानें:** कृत्रिम चट्टानों का निर्माण तरंग ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और तटरेखा की रक्षा कर सकता है।

- **पर्यावरण-अनुकूल ब्रेकवाटर:** प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मिश्रित सामग्रियों का उपयोग समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचाए बिना प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
- **जियो-ट्यूब स्थापना:** ओडिशा के पेंथा गांव जैसे क्षेत्रों में, कृत्रिम अवरोध बनाने के लिए जियो-ट्यूब स्थापित किए गए हैं जो तट को कटाव से बचाते हैं।
- **मैंग्रोव और शेल्टरबेल्ट वृक्षारोपण:** तट के किनारे मैंग्रोव तथा अन्य वनस्पति लगाने से तटरेखा को स्थिर करने और लहरों एवं तूफानी लहरों के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है।

### जागरूकता

- **समुदाय-संचालित संरक्षण:** स्थानीय समुदायों को पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए संरक्षण प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- **शिक्षा और जागरूकता अभियान:** तटीय पारिस्थितिक तंत्र के महत्व और कटाव के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से शमन उपायों के लिए सामुदायिक समर्थन को बढ़ावा मिल सकता है।

### निष्कर्ष

- भारत में तटीय कटाव को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान, सामुदायिक भागीदारी और सतत विकास प्रथाओं को जोड़ती है।
- प्रभावी शमन उपायों को लागू करके एवं जागरूकता को बढ़ावा देकर, भारत अपने तटीय क्षेत्रों की रक्षा कर सकता है और अपने तटीय समुदायों का कल्याण सुनिश्चित कर सकता है।

Source: DTE

## राष्ट्रीय बीज कांग्रेस (NSC) का 13वां संस्करण

### सन्दर्भ

- वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों ने तीन दिवसीय राष्ट्रीय बीज कांग्रेस (NSC) के 13वें संस्करण में भाग लिया।
  - NSC भारत और विश्व स्तर पर कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, किसानों और प्रतिनिधियों का एक वार्षिक संगम है।

### परिचय

- **थीम:** एक सतत बीज पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचार।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - देश में किसानों के लिए नवीन बीज प्रौद्योगिकियों पर अधिक कार्य करना।
  - बीज क्षेत्र में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना।
  - संकर और बायोफोर्टिफाइड फसलों, तनाव-सहिष्णु किस्मों और त्वरित प्रजनन चक्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - सतत बीज उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी।
- इन विचार-विमर्शों के परिणामों को खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्ण समर्थन के साथ लागू किया जाएगा।

### संकर फसलें (Hybrid Crops)

- संकर फसलें दो आनुवंशिक रूप से अलग-अलग पौधों, सामान्यतः विभिन्न किस्मों या प्रजातियों से, दोनों मूल पौधों के वांछनीय गुणों को संयोजित करने के लिए क्रॉसब्रीडिंग की प्रक्रिया के माध्यम से बनाई जाती हैं।

- **उद्देश्य:** ऐसी संतान पैदा करना जिसमें बेहतर गुण हों, जैसे कि बढ़ी हुई उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूखा सहनशीलता या बेहतर पोषण सामग्री।
- **चिंता:** संकर फसलें प्रायः ऐसे बीज पैदा नहीं करती हैं जिनमें मूल फसल के समान लाभकारी गुण बरकरार रहते हैं, इसलिए किसानों को प्रत्येक वर्ष नए बीज खरीदने की आवश्यकता होती है।

### बायोफोर्टिफाइड फसलें

- बायोफोर्टिफाइड फसलें वे फसलें हैं जिन्हें विशेष रूप से उनके पारंपरिक समकक्षों की तुलना में विटामिन, खनिज, या अमीनो एसिड जैसे आवश्यक पोषक तत्वों के उच्च स्तर के लिए तैयार किया गया है।
- यह पारंपरिक प्रजनन तकनीकों, आनुवंशिक संशोधन, या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तरीकों के माध्यम से किया जाता है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य फसलों के पोषण मूल्य में सुधार करना है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां आवश्यक पोषक तत्वों की कमी व्यापक है।
  - गोल्डन राइस को प्रोविटामिन ए (बीटा-कैरोटीन) के उच्च स्तर का उत्पादन करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है, जिसका लक्ष्य विटामिन ए की कमी को कम करना है।

The biofortified varieties have been licensed to various private seed companies and Farmers Producer Organizations (FPOs)

Sr. No.	Crop	Name of cultivar	No. of licenses
1.	Wheat	DBW 187	229
		DBW 303	204
		DBW 173	54
2.	Rice	DRR Dhan 45	4
		CR Dhan 310	2
3.	Maize	LQMH 1	2
4.	Pearl millet	HHB 299	5
		HHB 311	4
5.	Mustard	Pusa Mustard 30	6
		Pusa Double Zero Mustard 31	3
		Pusa Mustard 32	1
6.	Soybean	NRC 127	4
7.	Potato	Kufri Neekanth	5
		Kufri Manic	1
8.	Pomegranate	Sholapur Lal	7
<b>Total</b>			<b>531</b>

### मुख्य अंतर:

- हाइब्रिड/संकर फसलें विभिन्न किस्मों को क्रॉसब्रीडिंग करके उपज, लचीलापन या विकास विशेषताओं जैसे लक्षणों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- बायोफोर्टिफाइड फसलें प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषण सामग्री में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

### बायोफोर्टिफिकेशन के गुण:

- इसे कुपोषण दूर करने का सबसे सतत तरीका माना जाता है।
- यह प्राकृतिक रूप में पोषक तत्व प्रदान करता है।
- बायोफोर्टिफाइड भोजन किफायती है क्योंकि इसमें कोई अतिरिक्त कीमत शामिल नहीं है।

- 'बायोफोर्टिफाइड किस्में' 'पारंपरिक किस्मों' की तरह ही अधिक उपज देने वाली होती हैं, इसलिए किसानों को कोई हानि नहीं होती है।
- इसमें 'फूड फोर्टिफिकेशन' की तरह विस्तृत बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है।
- इसमें समृद्ध खाद्यान्न तैयार करने पर अतिरिक्त लागत शामिल नहीं है।

### सतत बीज उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल:

- **राष्ट्रीय बीज नीति (2002):** निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को बीज उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार और बीज वितरण की सुविधा के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **राष्ट्रीय जीन बैंक:** भविष्य में उपयोग के लिए पारंपरिक और स्वदेशी किस्मों को संरक्षित करते हुए, फसलों की आनुवंशिक विविधता को बनाए रखता है।
- **राज्य बीज बैंक:** देशी बीजों का संरक्षण और बीज विनिमय की सुविधा देकर स्थानीय किसानों को सहायता प्रदान करें।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM):** उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ चावल, गेहूं और दालों जैसी प्रमुख फसलों का उत्पादन बढ़ाना।
- **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):** यह पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए जलवायु-लचीले बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
- **राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन (NMOF):** जैविक बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, जैविक आदानों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है और बीज-बचत तकनीकों को बढ़ावा देता है।
- **किसान-उत्पादक संगठन (FPOs):** FPOs स्थानीय रूप से अनुकूलित बीजों के उत्पादन एवं वितरण की सुविधा प्रदान करते हैं, बीज प्रणालियों में किसानों की भागीदारी बढ़ाते हैं तथा बीज विविधता को बढ़ावा देते हैं।

Source: TH

### बागवानी उत्पादकता के लिए ADB के साथ भारत का समझौता

#### समाचार में

- भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने बागवानी किसानों के लिए प्रमाणित रोग-मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच में सुधार, फसल की उपज, गुणवत्ता एवं जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।

#### ऋण समझौते के बारे में

- **कार्यान्वयन:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के माध्यम से परियोजना को लागू करेगा।
- **समर्थन:** यह परियोजना भारत के आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (CPP) का समर्थन करती है, जो पौधों के स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ाने पर केंद्रित है।
  - यह भारत में बागवानी के लिए CPP को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक नियामक ढांचा और संस्थागत प्रणाली विकसित करेगा।
- यह परियोजना रोग-मुक्त नींव सामग्री को बनाए रखने के लिए स्वच्छ संयंत्र केंद्र स्थापित करेगी, जो उन्नत नैदानिक प्रयोगशालाओं से सुसज्जित होंगे और प्रशिक्षित विशेषज्ञों से सुसज्जित होंगे। यह निजी नर्सरी(nursery) के लिए उनकी रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमाणन योजना भी शुरू करेगा।
- **उद्देश्य:** परियोजना का उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य में सुधार करके फसल की उपज, गुणवत्ता और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन को बढ़ावा देना है।

- यह परियोजना बढ़ते तापमान और बदलते कीट एवं रोग व्यवहार के प्रभाव से निपटने के लिए पौधों के स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देकर किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में सहायता करती है।

### देश में बागवानी उत्पादन के बारे में

- भारत की अर्थव्यवस्था और पोषण के लिए महत्वपूर्ण बागवानी क्षेत्र को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है।
- 2023-24 (दूसरा अग्रिम अनुमान) में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 352.23 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2022-23 (अंतिम अनुमान) की तुलना में लगभग 32.51 लाख टन (0.91%) कम है।
  - 2023-24 (अंतिम अनुमान) में फलों, शहद, फूलों, वृक्षारोपण फसलों, मसालों एवं सुगंधित और औषधीय पौधों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है जबकि सब्जियों में कमी देखी गई है।
- भारत फलों, सब्जियों, चाय, मछली, गन्ना, गेहूं, चावल, कपास और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

### प्रभाव

- बागवानी क्षेत्र विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजित करके भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है।
- यह किसानों एवं श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है और खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा परिवहन जैसे संबंधित उद्योगों का समर्थन करता है।

### भारत में प्रमुख बागवानी पहल:

- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH):** यह देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए 2014-15 से लागू एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें फल, सब्जियां, जड़ एवं कंद वाली फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू और कोको शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM):** 2005 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देना, उत्पादन में सुधार, पोषण सुरक्षा और किसानों की आय में सुधार करना है।
- **बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (HCDP):** बागवानी समूहों के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य निर्यात बढ़ाना और भारतीय बागवानी उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:** मृदा परीक्षण और फसल-वार पोषक तत्व सिफारिशें प्रदान करती है, जिससे किसानों को सूचित निर्णय लेने, पैदावार में सुधार और इनपुट लागत कम करने में सहायता मिलती है।
- **उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH):** उत्तर पूर्व और हिमालयी क्षेत्रों में बागवानी विकास, किसानों की आजीविका में सुधार के लिए क्षेत्र-विशिष्ट फसलों और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

### चुनौतियां

- अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और परिवहन मुद्दों के कारण फसल के बाद महत्वपूर्ण हानि होती है।
- **बाज़ार तक पहुँच:** किसान प्रायः बाज़ारों तक पहुँचने और उचित मूल्य निर्धारण के साथ संघर्ष करते हैं, जिससे उनकी आय एवं लाभप्रदता प्रभावित होती है।

- **स्थिरता:** सतत कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करना और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना इस क्षेत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण है।

### भविष्य का दृष्टिकोण

- उच्च गुणवत्ता वाली उपज की बढ़ती घरेलू और वैश्विक मांग के साथ, भारत के बागवानी क्षेत्र का भविष्य आशाजनक लग रहा है।
- नवाचार और निवेश के साथ निरंतर सरकारी समर्थन, इस क्षेत्र के विकास को गति देगा।
- वर्तमान चुनौतियों का समाधान करके एवं अपनी क्षमता का लाभ उठाकर, भारत का बागवानी क्षेत्र अधिक ऊंचाई हासिल कर सकता है और अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

Source :TH

## संक्षिप्त ससमाचार

### साँची का महान स्तूप

#### सन्दर्भ

- मध्य प्रदेश के साँची में महान स्तूप में दो दिवसीय महाबोधि महोत्सव आयोजित किया गया।

#### साँची का महान स्तूप

- स्तूप एक बौद्ध स्मारक स्मारक है जिसमें सामान्यतः बुद्ध या अन्य संतों के पवित्र अवशेष होते हैं।
- आदर्श स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना है, जिसकी उत्पत्ति भारत में पाए जाने वाले पूर्व-बौद्ध दफन टीलों से की जा सकती है।
- **स्थापित:** इस स्तूप का निर्माण ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में मौर्य वंश के सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद धर्म परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था।
  - इसका निर्माण बुद्ध के अवशेषों को रखने और बौद्ध पूजा के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए किया गया था।
- **संरचना:**
  - महान स्तूप पत्थर और ईंट से बना एक अर्धगोलाकार गुंबद है, जिसकी केंद्रीय संरचना एक बड़ा, ऊंचा मंच है जिसमें बुद्ध के अवशेष हैं।
  - इसके शीर्ष पर त्रिछत्र, या 'छत्रवेली' धारण करने के लिए एक 'हर्मिका' है, जो बौद्ध धर्म के तीन रत्नों - बुद्ध, धर्म और संघ का प्रतिनिधित्व करता है।
  - गुंबद के ऊपर, एक स्तंभ जैसी संरचना है जिसे छत्र कहा जाता है, जो बुद्ध की उपस्थिति और ज्ञान का प्रतीक है।



- स्तूप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और विश्व भर के बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थल है।

Source: AIR

## पेरू में नाज़्का जियोग्लिफ़्स (Nazca Geoglyphs)

### समाचार में

- हाल के AI और ड्रोन तकनीक में उन्नति ने नए नाज़्का जियोग्लिफ़्स की खोज को तेजी से बढ़ावा दिया है।
  - ये खोजें नाज़्का संस्कृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो लिखित अभिलेखों के बजाय अपने अनुष्ठानिक और औपचारिक महत्व के लिए जानी जाती हैं।

### नाज़्का लाइन्स के बारे में

- वे पेरू के लीमा से 400 किमी दक्षिण में स्थित हैं और बंजर नाज़्का पम्पा पर पाए जाने वाले प्राचीन जियोग्लिफ़ हैं।
  - चट्टानों और पृथ्वी को हटाकर नकारात्मक छवियाँ बनाने के लिए जियोग्लिफ़ बनाए गए, जो रेगिस्तान की शुष्क और वायु रहित स्थितियों के कारण संरक्षित हैं।
  - वे 2,000 वर्ष से अधिक पुराने हैं, और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु ने उन्हें कटाव से बचाया है।
- 1920 के दशक में खोजे गए, ये ज्योग्लिफ़ शुरू में अज्ञात थे, लगभग एक शताब्दी में लगभग 430 की पहचान की गई थी।



### पेरू

- **स्थान:** यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है।
  - इसकी सीमाएँ इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया और चिली से लगती हैं।
- **भौगोलिक विशेषताएं:** पेरू एंडीज़ तक विस्तारित है, जो विश्व की सबसे लंबी उजागर पर्वत श्रृंखला है।
  - देश की सबसे ऊँची चोटी माउंट हुआस्करन है।
  - प्रमुख नदियाँ अमेज़न, पुरुस, जुरुआ आदि हैं। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर एंडीज़ पहाड़ों में मीठे पानी की एक बड़ी झील है। इसे प्रायः विश्व की सबसे ऊँची नौगम्य झील कहा जाता है।

Source: IE

## ऑक्सफोर्ड ने प्रगति(PRAGATI) प्लेटफार्म की सराहना की

### समाचार में

- ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्ईद बिजनेस स्कूल (SBS) के एक हालिया अध्ययन ने PRAGATI(प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सिस्टम की सराहना की है।

## अध्ययन के निष्कर्ष

- **बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रभाव:** भूमि अधिग्रहण और अंतर-मंत्रालयी समन्वय जैसी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करते हुए, 205 बिलियन डॉलर की 340 परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया गया।
  - सड़क, रेलवे, जल आपूर्ति और बिजली वितरण जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचा सेवाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया गया।
- **तकनीकी नवाचार:** कुशल निर्णय लेने और परियोजना त्वरण के लिए वास्तविक समय डेटा, ड्रोन फ़ीड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ उठाया गया।
  - हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय मंजूरी को सुव्यवस्थित करके स्थिरता को शामिल किया गया।
- **आर्थिक परिवर्तन:** RBI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी स्टडीज के अनुसार, प्रगति के तहत बुनियादी ढांचे पर व्यय करने पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये पर GDP गुणक प्रभाव ₹2.5 से ₹3.5 होता है।
- **सामाजिक लाभ:** आवश्यक सेवाएं प्रदान करके और विकास में समावेशिता सुनिश्चित करके लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया गया।
  - टीम इंडिया की मानसिकता को बढ़ावा देकर और हितधारकों के बीच जवाबदेही को प्रोत्साहित करके नौकरशाही जड़ता को संबोधित किया गया।
- **वैश्विक विकास के लिए सबक:** मध्य-आय जाल का सामना कर रहे देशों के लिए एक शासन मॉडल प्रदान करता है।

## PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) प्लेटफॉर्म के बारे में

- **लॉन्च:** प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में प्रस्तुत किया गया।
- **प्रगति के मुख्य उद्देश्य:**
  - परियोजना कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए।
  - विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
  - शासन और परियोजना निष्पादन में जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- **प्रगति की मुख्य विशेषताएं:**
  - वास्तविक समय की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का एकीकरण।
  - प्रधानमंत्री और राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीधा संवाद।
  - प्रशासनिक सिलोस को हटाने और समन्वय में सुधार पर ध्यान केंद्रित।

Source: TOI

## रबी फसल के लिए संभावनाएँ और चिंताएँ

### समाचार में

- रबी की फसल के मौसम को निम्न कारणों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:
  - अक्टूबर में उच्च तापमान के कारण बुआई में देरी हुई और फसल के अंकुरण पर प्रभाव पड़ा।
  - डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक की कमी, जिसने अस्थायी रूप से रोपण में बाधा उत्पन्न की है।

### धीमी प्रगति के पीछे कारण

- **उच्च अक्टूबर तापमान:** तापमान सामान्य से 0.68 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिससे बुआई में देरी हुई और अंकुरण कम हुआ, विशेषकर जीरा (cumin) और अन्य मसालों जैसी फसलों में।

- **उर्वरक की कमी:** DAP उर्वरक की अनुपलब्धता ने किसानों के लिए रोपण कार्यक्रम को बाधित कर दिया।
- **बुआई में देरी:** उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में किसानों ने सामान्य से देर से (मध्य अक्टूबर के बजाय 20-22 अक्टूबर) बुआई शुरू की।

### रबी फसलें

- **बुआई की अवधि:** अक्टूबर के आसपास, लौटते मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के दौरान।
- **कटाई की अवधि:** अप्रैल से मई (ग्रीष्म ऋतु)।
- **जलवायु आवश्यकताएँ:** बीज अंकुरण के लिए गर्म जलवायु।
  - फसल की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु।
- **वर्षा:** वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर नहीं; सिंचाई का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है।
- **प्रमुख फसलें:** गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों।

### अन्य उगाई जाने वाली फसलें

- **खरीफ़ फसलें:**
  - **बुआई की अवधि:** दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान (मई के अंत से जून की शुरुआत तक)।
  - **कटाई की अवधि:** मानसून के बाद की बारिश (अक्टूबर की शुरुआत)।
  - **जलवायु आवश्यकताएँ:** विकास के लिए भारी वर्षा और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है।
  - **प्रमुख फसलें:** चावल, मक्का, दालें (उड़द, मूंग दाल), बाजरा, कपास।
- **जायद फसलें:**
  - **बुआई और कटाई की अवधि:** मार्च से जुलाई (रबी और खरीफ मौसम के बीच)।
  - **जलवायु आवश्यकताएँ:** पर्याप्त जल आपूर्ति के साथ गर्म मौसम।
  - **प्रमुख फसलें:** मौसमी फल (जैसे तरबूज, खरबूजा), सब्जियाँ और चारा फसलें।

Source: TH

### विंडफॉल टैक्स /अप्रत्याशित कर (Windfall Tax)

#### समाचार में

- सरकार ने कच्चे तेल, एटीएफ, पेट्रोल और डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित कर को समाप्त कर दिया।

#### विंडफॉल टैक्स/अप्रत्याशित कर के बारे में

- अप्रत्याशित कर उन उद्योगों या कंपनियों पर लगाया जाता है जो अनुकूल बाजार स्थितियों के कारण असाधारण लाभ का अनुभव करते हैं, न कि उनके स्वयं के प्रयासों या नवाचार के कारण।
- ये कर सरकारों को सार्वजनिक परियोजनाओं को निधि देने, राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने, या धन असमानताओं को संबोधित करने के लिए इन लाभों का हिस्सा प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
- जुलाई 2022 में प्रस्तुत किया गया, जब रूस-यूक्रेन युद्ध सहित भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें उभरीं।
- इसने घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों और पेट्रोलियम उत्पादों (जैसे, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ) के निर्यातकों को लक्षित किया, जिन्हें ऊंची वैश्विक कीमतों से लाभ हुआ।

#### इसे क्यों समाप्त किया गया?

- **वैश्विक तेल की कीमतें स्थिर होना:** कच्चे तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, जिससे कर की आवश्यकता कम हो गई है।

- **घरेलू और निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा देना:** तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करता है।

**Source: ET**

## वधावन बंदरगाह

### सन्दर्भ

- महाराष्ट्र में दहानू के पास वधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह निर्माणाधीन है।

### परिचय

- **विकास:** जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया।
- इसे 2034 तक पूरा करने का लक्ष्य है, इसके विश्व के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होने की संभावना है।
- इसके पूरा होने पर यह भारत के कंटेनर व्यापार को वर्तमान स्तर से दोगुना कर देगा।
- ग्रीनफील्ड परियोजना का तात्पर्य है कि बंदरगाह का निर्माण या विस्तार पहले से अविकसित भूमि पर होता है।
- ब्राउनफील्ड परियोजनाएँ उस भूमि पर बनाई जाती हैं जिसका पहले उपयोग किया जा चुका है और प्रायः पुनर्विकास या पुनर्वास की आवश्यकता होती है।

**Source: TH**

## अभ्यास सिनबैक्स (Exercise CINBAX)

### सन्दर्भ

- भारतीय सेना और कम्बोडियन सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास CINBAX का पहला संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड, पुणे (भारत) में शुरू हुआ।

### परिचय

- अभ्यास CINBAX एक योजना अभ्यास है जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत आयोजित संयुक्त आतंकवाद विरोधी (CT) अभियानों का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह अभ्यास तीन चरणों में किया जाएगा और इसमें सूचना संचालन, साइबर युद्ध, हाइब्रिड युद्ध, रसद और हताहत प्रबंधन, HADR(मानवीय सहायता और आपदा राहत) संचालन आदि पर चर्चा शामिल होगी।

**Source: PIB**

## अग्नि योद्धा अभ्यास (XAW-2024) [Exercise AGNI WARRIOR (XAW-2024)]

### सन्दर्भ

- भारतीय सेना और सिंगापुर सेना ने महाराष्ट्र (भारत) में अभ्यास अग्नि योद्धा (XAW) के 13वें संस्करण का समापन किया।

### परिचय

- 2004 से भारत में आयोजित, XAW सेना द्विपक्षीय समझौते के दायरे में आयोजित किया जाता है, और सिंगापुर एवं भारत के बीच मधुर तथा लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों पर प्रकाश डालता है।

- XAW-2024 का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक बहुराष्ट्रीय बल के रूप में संयुक्तता प्राप्त करने के लिए अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को अधिकतम करना था।

Source: PIB

## अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट (AGWP)

### समाचार में

- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पार्टियों का 16वां सम्मेलन (COP16) रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है, यह पहली बार है कि इस कार्यक्रम की मेजबानी पश्चिम एशिया में की गई है।
  - COP16 सऊदी अरब द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय कार्यक्रम है, जो सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज को स्थायी भूमि प्रबंधन पर सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

### अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट (AGWP) की प्रस्तुति

- भारत AGWP प्रस्तुत करेगा, जिसका उद्देश्य उत्तर-पश्चिमी भारत के चार राज्यों में 1.15 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करना है।
- **अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट (AGWP) की विशेषताएं:** यह परियोजना हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली हिल रेंज के आसपास 5 किमी बफर क्षेत्र को कवर करती है।
- **राष्ट्रीय लक्ष्य:** यह परियोजना 2030 तक अतिरिक्त 2.5 बिलियन टन कार्बन सिंक बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के भारत के प्रयास का हिस्सा है।
- **व्यापक प्रभाव:** यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं में योगदान देती है जैसे:
  - UNCCD(मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन),
  - CBD(जैविक विविधता पर सम्मेलन),
  - UNFCCC(जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन)।
- **AGWP के उद्देश्य और विशेषताएं:** यह परियोजना मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने पर केंद्रित है।
  - यह स्वदेशी प्रजातियों के वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और उन्नत जल प्रबंधन रणनीतियों को एकीकृत करता है।

Source: DD News

## नागालैंड राज्य दिवस

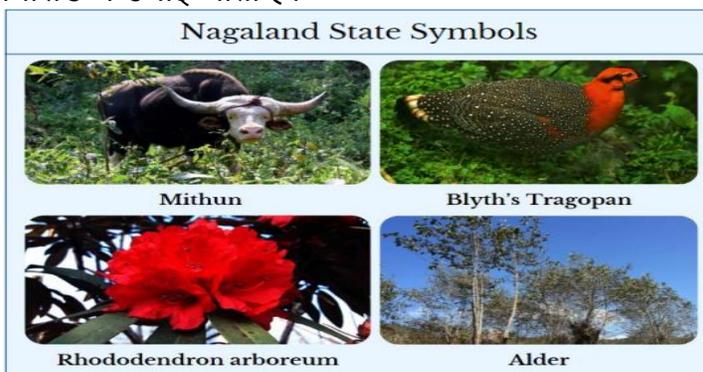
### सन्दर्भ

- 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया।

### नागालैंड के बारे में: मुख्य तथ्य

- **गठन:** राज्य का गठन 1 दिसंबर, 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुआ था और तब से यह दिन प्रतिवर्ष नागालैंड राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
  - 1957 तक, जिस क्षेत्र को आज हम नागालैंड कहते हैं, वह असम राज्य का एक जिला मात्र था, जिसे लोग 'द नागा हिल्स' के नाम से जानते थे।

- **सीमा:** सात बहन राज्यों में से एक, नागालैंड पश्चिम में असम, पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम का कुछ हिस्सा और दक्षिण में मणिपुर से घिरा है।
- **आधिकारिक भाषा:** नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है जबकि नागामीज़, एक प्रकार की पिजिन असमिया, सामान्य भाषा बन गई है।
- **जनजातियाँ:** नागालैंड में 17 प्रमुख जनजातियाँ रहती हैं: अंगामी, एओ, चाखेसांग, चांग, कचारी, खियामनियुंगन, कोन्याक, कुकी, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संगतम, सुमी, तिखिर, यिमखिउंग और ज़ेलियांग।
- **हॉर्नबिल महोत्सव:** इसे 'त्योहारों का त्योहार' भी कहा जाता है और इसका नाम हॉर्नबिल (धनेश पक्षी) के नाम पर रखा गया है, यह 10 दिवसीय कार्यक्रम नागालैंड की स्वदेशी योद्धा जनजातियों की परंपराओं, व्यंजनों, जीवन शैली और नृत्यों का जश्न मनाता है।
- **अमूर बाज़:** नागालैंड को 'विश्व की फाल्कन राजधानी' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अमूर बाज़ के लिए प्राथमिक पड़ाव स्थल है।
- **अर्थव्यवस्था:** नागालैंड मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी 71% आबादी कृषि पर निर्भर है।
- **नागा मिर्च:** स्कोविल हीट यूनिट्स (SHUs) के आधार पर विश्व की सबसे तीखी मिर्चों में से एक मानी जाने वाली मिर्च नागालैंड में उगाई जाती है।



Source: PIB

